भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3278
दिनांक 08.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

एलएसी पर भारत और चीन की सेनाओं का पीछे हटना

3278. **श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारत और चीन की सेनाएं पिछले नौ महीनों से पीछे हटी हुई हैं

जबकि तनाव कम करने का कार्य अभी शेष है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तनाव कम करने के लिए कोई नया रोडमैप तैयार किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और चीन के बीच हाल ही में कोई द्विपक्षीय वार्ता हुई है और यदि हाँ, तो उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर दोनों पक्षों में आम महमति है और पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी द्विपक्षीय वार्ताएँ हुई हैं,

(घ) क्या 2020 से एलएमी पर तैनात सैन्य बलों की मौजूदगी बनी हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने चीन द्वारा प्रतिबंधात्मक व्यापार उपाय लागू करने और महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंधों का मुद्दा उठाया है और यदि हाँ, तो समाधान पर प्राप्त प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क से ङ) भारत और चीन ने 21 अक्टूबर 2024 को देपसांग और डेमचोक में भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था पर एक करार किया, जिसके परिणामस्वरूप सैनिकों की वापसी हुई। तब से यह करार सहमत तौर-तरीकों और समय-सीमा के अनुसार प्रभावी और कार्यान्वित किया गया है। 21 अक्टूबर 2024 से पहले हुए सैनिकों की वापसी संबंधी करारों की शर्तें पूर्वी लद्दाख के संबंधित क्षेत्रों में लागू हैं। भारत और चीन ने विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री सहित विभिन्न स्तरों पर तनाव कम करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है।

अक्टूबर 2024 तक, भारत और चीन सहयोग और समन्वय कार्य तंत्र (डबल्यूएमसीसी) और वरिष्ठ सर्वोच्च सैन्य कमांडरों की बैठक (एसएचएमसी) तंत्र के माध्यम से एलएसी पर सैनिकों की वापसी के मुद्दों को हल करने के लिए लगे रहे। वर्ष 2024 में, सैनिकों की वापसी के बाद से, भारत-चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता और डब्ल्यूएमसीसी जैसे सीमा-संबंधी मुद्दों को हल करने के तंत्रों के अलावा, दोनों पक्षों ने संबंधों को स्थिर और पुन:स्थापित करने के लिए कई अन्य बैठकें की हैं, जिनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा, सीधी उड़ान संपर्क, सीमा पार नदियों सहित जन-केंद्रित गतिविधियों को प्राथमिकता दी गई है और राजनयिक संबंध स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाने संबंधी गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं। पिछले वर्ष से, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश सचिव और उनके चीनी समकक्षों के बीच बैठकें हुई हैं।

विदेश मंत्री और विदेश सचिव ने अपने-अपने समकक्षों के साथ प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों और आर्थिक सहयोग में आने वाली बाधाओं से संबंधित मुद्दों को उठाया है। इन मामलों पर कार्यकारी स्तर पर भी चर्चा हुई है।

*****